tor will continue to be so reserved. [Medium and large scale industrial undertakings including multinationals will have to obtain an industdrial licence for the manufacture of articles reserved for small scale sector. Their applications will be considered by the Government on merits and licnece will be issued only if they undertake to export at least 75 per cent of their production.

Action against the economic offences

1611. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have asked recently the State Governments to gear up their vigilance and enforcement agencies to take firm action against hoarding, blackmarketing and similar economic offences;

(b) if so, whether despite instructions from Government, the prices of essen tial commodities are rising and people are unable to get consumer products at a reasonable price;

(c) whether poor quality goods are supplied through Fair Price Shops; and

(d) if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Yes. Sir.

(b) There has been a mixed behaviour of the price index of essentia! commodities during the last three months. The increase in prices of some of these commodities sould be attributed to gap in demand and supply, seasonal factors and an increase in aggregate money supply.

(c) and (d) Central Government makes available, to the State Governments and Union Territory Administrations, foodgrains of Fair Average Quality (FAQ), for distribution under Public Distribution System (PDS). State Governments/UT Administrations have also been requested to ensure that goods of proper quality are supplied through Fair Price Shops.

ग्रामीण विकास तथा इसमें बाधायें

1612. डा० अबरार अहमद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास के संबंध में सरकार की योजनाएं क्या हैं ; और

(ख) ग्रामीण विकास कार्य में मुख्य बाधाएं क्या हैं तथा उन्हें किस प्रकार हटाया जा रहा है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) ग्रामीण विकास हेतु सरकार की योजना में ग्रामीण गरीबी को दूर करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने, पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने पर ध्यान दिया जाता है । इस प्रयोजन हेतु गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं ।

(ख) ग्रामीण विकास के कार्यों में आने वाली मुख्य बाधाओं में ये शामिल हैं :—लोगों की पर्याप्त भागीदारी का न होना, इन कार्यक्रमों का अन्य विकास योजनाओं के साथ पूरी तरह समन्वय न होना, कार्यक्रमों के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का रख-रखाव न हो पाना तथा कभी-कभी पात्र गरीबों तक इन कार्यक्रमों का न पहुंच पाना । ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में खामियों का पता लगाने के लिये अनेक समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन करवा रहा है । सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर कार्यक्रमों में पाई गई खामियों को दूर करने के लिये सुधारात्मक/उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ।